3

अविश्वास प्रस्ताव के बाद जारी है भुगतान

5

परिश्रम, निष्ठा और अवसरों का प्रतिबिंब

6

दिवाली बाद गहराया देशव्यापी प्रदूषण

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 25 प्रति सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम बनी, लेकिन छाई असंतोष की छाया

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश की राजनीति इन दिनों फिर एक बार सियासी हलचल से भरी है। भारतीय जनता पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नई टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने 15 नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में दायित्व सौंपे हैं, जिससे संगठनात्मक गति तो मिली है, पर साथ ही नए समीकरणों और असंतोष की लहरें भी तेज हो उठी हैं। हेमंत खंडेलवाल के इस निर्णय से पार्टी के भीतर एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या भाजपा इस टीम से 2028 के विधानसभा चुनाव तक संगठन को एकजुट रख पाएगी या फिर यह असंतोष भीतर ही भीतर एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा?

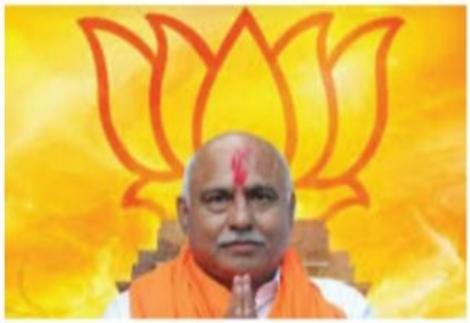

क्या 2028 की अग्नि-परीक्षा में सार्थक साबित होगी खंडेलवाल की टीम?

खंडेलवाल की टीम संतुलन साधने की कोशिश

भाजपा ने इस बार कार्यकारिणी में नए और पुराने चेहरों का मिश्रण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसमें क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समीकरण और अनुभव का ध्यान रखा गया है। लेकिन हर राजनीतिक नियुक्ति की तरह यहाँ भी सभी को संतुष्ट कर पाना संभव नहीं था। कई वरिष्ठ नेता और उनके समर्थक खुद को इस समीकरण से बाहर पाकर नाराज हैं। संगठन के भीतर यह असंतोष उतना मुखर नहीं है, जितना फुसफुसाहटों में है और यही फुसफुसाहटें किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकेत होती हैं।

सिंधी समाज और मिश्रा खेमे की नाराजगी

भोपाल में सिंधी समाज से लेकर पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों तक में नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती जल्द

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद वित्त विभाग की भी मिली मंजूरी, पांच हजार नए पदों पर भर्ती के लिए जल्द जारी होगा आदेश

-विजया पाठक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य शासन के वित्त विभाग ने आज 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की सहमति प्रदान कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को मजबूत बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य की प्रगति की नींव होती है और छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चे तक ज्ञान और अवसर दोनों पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह भर्ती न केवल शिक्षण व्यवस्था को गति देगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। मुख्यमंत्री

विष्णुदेव साय ने वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति को 'नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम' बताया। 5000 पदों हेतु शिक्षा विभाग शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। इन पदों की पूर्ति से ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होगी, जिससे शिक्षण की निरंतरता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य

राज्य शासन ने पिछले कुछ महीनों में शिक्षा सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। विद्यालय भवनों के निर्माण, डिजिटल शिक्षा सामग्री के प्रसार, और शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में शिक्षकों की कमी लंबे समय से एक प्रमुख चुनौती रही है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सीमित थी। नई भर्ती से इन क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे बच्चों को अब अपने ही गाँव और क्षेत्र में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। (शेष पेज 6 पर)

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बढ़ते प्रहार

पत्रकार आनंद पांडे और हरीश दिवेकर की गिरफ्तारी के मायने क्या?

-विजया पाठक

भारतीय लोकतंत्र की आत्मा उसकी संस्थाओं में निहित है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीन स्तंभ लोकतांत्रिक ढांचे की नींव हैं, परंतु इन स्तंभों के साथ पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा गया है, जिसने सदैव समाज की नब्ज टटोलने और सत्ता को आईना दिखाने का कार्य किया है। परंतु, विडंबना यह है कि आज वही चौथा स्तंभ लगातार हमलों और दमन के दौर से गुजर रहा है। पिछले एक दशक में मीडिया की स्वतंत्रता पर जो प्रहार हुए हैं, वे यह दर्शाते हैं कि सत्ता के गलियारों में कलम की ताकत से भय व्याप्त है। जहां भी पत्रकारिता ने सत्ताधारी वर्ग के भ्रष्टाचार, कदाचार या दोहरे चरित्र को उजागर किया है, वहां सत्ता ने अपनी पूरी ताकत से उसे दबाने का प्रयास किया है। मध्यप्रदेश में हाल की घटना इसका ताजा उदाहरण है, जब वरिष्ठ पत्रकार आनंद पांडे और हरीश दिवेकर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पत्रकारों ने राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा किया था। (शेष पेज 2 पर)

पत्रकार आनंद पांडे और हरीश दिवेकर की गिरफ्तारी के मायने क्या?

(पेज 1 का शेष)

सत्ता की असहजता इतनी बढ़ी कि पत्रकारों को गिरफ्तार करने जैसे कदम उठा लिए गए। यह न केवल लोकतंत्र पर धब्बा है, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता का अपमान भी है। राजनीति का यह नया चेहरा बेहद चिंताजनक है। हालांकि लगभग 6 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों पत्रकारों को राजस्थान पुलिस ने छोड़ दिया।

पत्रकारिता प्रहरी है, उसे कुचलना लोकतंत्र के हित में नहीं

राजस्थान की यह घटना कोई अलग मामला नहीं है। चाहे दिल्ली, मध्यप्रदेश या राजस्थान हर जगह सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता पत्रकारों की कलम से घबराए दिखाई देते हैं। पत्रकारों पर मुकदमे, गिरफ्तारी और धमकी अब सामान्य राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। यह प्रवृत्ति न केवल मीडिया की आजादी को सीमित कर रही है, बल्कि जनता के उस अधिकार को भी छीन रही है जिसके तहत उसे सच जानने का हक है। पत्रकारिता का उद्देश्य हमेशा सत्ता के निर्णयों पर प्रश्न उठाना रहा है। यही प्रश्न लोकतंत्र को संतुलित रखता है। परंतु जब सवाल करने वाला ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, तो इसका अर्थ साफ है सत्ता अब जवाबदेही से बचना चाहती है। यह स्थिति केवल विपक्ष या किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पूरी प्रणाली के लिए खतरनाक है। लोकतंत्र में पत्रकार की भूमिका प्रहरी की होती है, जो जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करता है। पर जब प्रहरी की आँखों पर ही पट्टी बांध दी जाए, तो व्यवस्था अंधी हो जाती है। दुर्भाग्य से, आज सत्ता में बैठे लोगों को मीडिया का "नियंत्रित संस्करण" चाहिए जो वही कहे, जो वे सुनना चाहते हैं। ऐसे दौर में स्वतंत्र पत्रकारिता किसी क्रांतिकारी कदम से कम नहीं रह गई है। पांडे और दिवेकर जैसे पत्रकारों ने जब सत्ता की परतें खोलनी शुरू कीं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि सच अब सत्ता के लिए असुविधाजनक हो चुका है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह प्रवृत्ति दोहरी है। जब सत्ता में कोई पार्टी होती है, तो वह मीडिया की स्वतंत्रता पर लगाम कसती है और जब वही पार्टी विपक्ष में जाती है तो वही मीडिया "लोकतंत्र की आत्मा" बन जाती है। यह दोहरा चरित्र भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संकट है।

क्या पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर प्रहार अब सामान्यीकृत हो चुका?

सवाल यह भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट और अन्य संवैधानिक संस्थाएं इस पर मौन क्यों हैं? क्या पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर प्रहार अब सामान्यीकृत हो चुका है? यदि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो फिर पत्रकारों को इस अधिकार से वंचित करना न केवल असंवैधानिक बल्कि अमानवीय भी है। इतिहास गवाह है कि जब-जब सत्ता ने कलम को कैद करने का प्रयास किया है, तब-तब सत्य और विचार की ताकत और अधिक प्रखर होकर उभरी है। हर युग में सत्ता ने कलम को झुकाने की कोशिश की, परंतु कलम हर बार और तेजी से उठी है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आलोचकों को डराने-धमकाने का प्रयास किया। मैंने भी महादेव सटटा ऐप को उजागर किया और इसके बदले कई बार छत्तीसगढ़ की पुलिस मुझे गिरफ्तार करने भोपाल आयी। छग के पत्रकार सुनील नामदेव को भी काफी प्रताडित किया। मप्र में भी पिछले कुछ दिनों में भ्रष्टाचार को उजागर करने के मामलों में करीब 08 पत्रकारों को गिरफ्तार किया। लेकिन जनता ने तय किया कि भ्रष्टाचार और दमन की राजनीति को जवाब देना है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है जब जनता ही न्यायाधीश बन जाती है। आज आवश्यकता है कि पत्रकारिता को "देशद्रोह" या "मानहानि" की परिभाषा में बांधने की जगह उसे लोकतंत्र की आत्मा के रूप में सम्मान दिया जाए। लोकतंत्र तभी स्वस्थ रह सकता है जब हर पत्रकार बिना भय के सच कह सके, हर नागरिक सवाल पूछ सके और हर सत्ता जवाब देने को बाध्य हो। पत्रकारिता को दबाने के प्रयास, चाहे वे किसी भी सरकार द्वारा किए जाएं, अंततः उसी सरकार की साख को कमजोर करते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है और जब कलम जनता के पक्ष में चलती है, तो कोई सत्ता उसे रोक नहीं सकती। लोकतंत्र की रक्षा तभी संभव है जब कलम स्वतंत्र रहे। आनंद पांडे और हरीश दिवेकर की गिरफ्तारी जैसे उदाहरण हमें चेताते हैं कि यदि आज हमने इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो कल यह प्रहार हर उस नागरिक पर होगा जो सच बोलने का साहस रखता है। इसलिए अब समय आ गया है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं आगे आएं, पत्रकारिता की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करें क्योंकि जब चौथा स्तंभ डगमगाता है, तो पूरा लोकतांत्रिक ढांचा हिल जाता है। सत्ता के इस भयभीत व्यवहार को रोकना अब आवश्यक है। पत्रकारिता का दमन किसी पार्टी या व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र पर हमला है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम बनी, लेकिन छाई असंतोष की छाया

(पेज 1 का शेष)

सिंधी समाज का तर्क है कि प्रदेश में भाजपा को इस समुदाय ने लगातार समर्थन दिया है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर उन्हें अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उधर, डॉ. मिश्रा के समर्थक इस बात से असहज हैं कि उनके नजदीकी नेताओं को कार्यकारिणी में वह स्थान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। राजनीति में यह असंतोष असामान्य नहीं है लेकिन जब असंतोष के केंद्र में ऐसे नेता हों, जिनका प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत है, तो मामला केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी हो जाता है।

भाजपा के लिए दोहरी चुनौती

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाने की है। एक ओर उन्हें संगठन की नई ऊर्जा बनाए रखनी है, दूसरी ओर नाराज नेताओं को साथ लेकर चलना है। भाजपा का संगठनात्मक ढाँचा अनुशासन और सामूहिक निर्णय पर आधारित माना जाता है, लेकिन जब भीतर ही भीतर असंतोष का स्वर उभरता है, तो उसका असर कार्यकर्ता स्तर तक जाता है। चुनावों से पहले यह स्थिति भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। पार्टी भले ही सत्ता में मजबूत स्थिति में हो, लेकिन अंतर्कलह यदि सार्वजनिक हुई तो विपक्ष को बड़ा हथियार मिल सकता है।

खंडेलवाल के नेतृत्व की परीक्षा

हेमंत खंडेलवाल अपेक्षाकृत युवा, ऊर्जावान और संगठन में सक्रिय माने जाते हैं। उन्हें यह दायित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की टीम की सहमति से मिला है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि वे नई ऊर्जा, संवाद और कनेक्टिविटी के माध्यम से संगठन को पुनः गतिशील बना सकते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उनके सामने परिस्थितियाँ आसान नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, और अन्य दिग्गज नेताओं के प्रभाव वाले प्रदेश में कार्यकारिणी की रचना करना ऐसा ही है जैसे बर्फ पर कदम रखते हुए संतुलन बनाना।

संगठन की परंपरा और अपेक्षाएँ

भाजपा हमेशा से "संगठन सर्वोपरि" की नीति पर चलती आई है। परंतु, जब टिकट वितरण, पद या कार्यकारिणी की बात आती है, तो सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की जटिलता सामने आ जाती है। यही जटिलता इस बार भी देखने को मिली। पार्टी की कोशिश रही कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, लेकिन राजनीतिक आकांक्षाएँ हर नियुक्ति से जुड़ी होती हैं। ऐसे में संगठन को अपेक्षित सामंजस्य बनाए रखने के लिए संवाद ही सबसे बड़ा साधन होता है। यही संवाद अब खंडेलवाल की अगली रणनीति का हिस्सा बनना चाहिए।

असंतोष का राजनीतिक गणित

राजनीति में नाराजगी कोई स्थायी स्थिति नहीं होती यह परिस्थितियों से बनती और बिगड़ती है। लेकिन जब नाराज समर्थक अपनी ऊर्जा को निष्क्रियता में बदल दें, तो उसका असर सीधे बूथ स्तर पर दिखाई देता है। भाजपा के पास आज भी सबसे मजबूत संगठनात्मक ढाँचा है, लेकिन यही ताकत तभी प्रभावी रहती है जब सभी गुट एक दिशा में काम करें। यदि यह असंतोष समय रहते शांत नहीं हुआ, तो आगामी नगरीय और स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। प्रदेश में कांग्रेस लगातार सक्रियता दिखा रही है और अगर भाजपा का ध्यान आंतरिक प्रबंधन में ही अटक गया, तो विपक्ष को खुला मैदान मिल सकता है।

आगामी चुनावी समीकरण पर प्रभाव

आगामी विधानसभा चुनाव 2028 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। भाजपा के लिए यह समय संगठन को एकजुट करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा "विकास और स्थिरता" के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है, पर राज्य स्तर पर नेतृत्व की असहमति इस अभियान को कमजोर कर सकती है। खंडेलवाल के सामने यही कसौटी है क्या वे असंतोष को संवाद और समावेशन से दूर कर पाएंगे? यदि उन्होंने जल्द ही नाराज नेताओं को साधने में सफलता प्राप्त की, तो संगठन और मजबूत होगा। यदि नहीं, तो यह असंतोष धीरे-धीरे स्थानीय स्तर पर सक्रिय असंतुष्टि में बदल सकता है।

संवाद से ही निकला है समाधान

भाजपा का इतिहास बताता है कि पार्टी ने हमेशा संगठनात्मक अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि हर संकट में भाजपा ने खुद को संभाला है। लेकिन इस बार चुनौती आंतरिक है असंतोष का स्वर भीतर से उठ रहा है। हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। उन्हें न केवल संगठन को सक्रिय रखना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस न करे। यदि वे इस चुनौती को अवसर में बदल सके संवाद, सम्मान और सहभागिता के माध्यम से तो भाजपा न केवल एकजुट होगी, बल्कि भविष्य के चुनावों में पहले से कहीं अधिक मजबूती से उभरेगी। यदि यह असंतोष जड़ें पकड़ गया, तो वही भाजपा जिसे अनुशासन का प्रतीक माना जाता है, अपने भीतर मतभेदों की तपिश महसूस कर सकती है।

'अवैध कॉलोनियों का खेल' जोरों पर, प्रशासन की नाक के नीचे नियमों को दरकिनार कर बेचे जा रहे प्लॉट

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरीकला। देवरी नगरपालिका और आसपास के ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का कारोबार प्रशासन की कथित मिलीभगत से धड़ल्ले से चल रहा है। कॉलोनाइजरों द्वारा शासन के मापदंडों और रेरा के नियमों को खुलेआम दरकिनार कर बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, और इन कॉलोनियों में प्लॉट बेचे जा रहे हैं।

इन क्षेत्रों में कट रही हैं अवैध कॉलोनियां

नगर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में भू-माफिया सक्रिय हैं। सरकारी अस्पताल के आसपास, फोरलाइन के नजदीक, रहली मार्ग के पास, ग्राम रजौला में बीना-बारहा रोड, सहजपुर रोड, सीएम राइज स्कूल के आसपास, पुराना बायपास रोड, और घुघरी रोड के पास धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटकर प्लाट बेचे जा रहे हैं।

रेरा के नियमों का खुला उल्लंघन

कॉलोनी काटने के लिए रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट यानी रेरा के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, लेकिन देवरी में इन महत्वपूर्ण नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। रेरा के नियमों का पालन न होने से न केवल क्रेता (खरीदने वाले) धोखे का शिकार हो सकते हैं, बल्कि इन अवैध कॉलोनियों के कारण क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है और आम जनता की सुरक्षा एवं विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

ठोस कार्रवाई की मांग, मुख्यमंत्री के आदेश पर नजर

इस गंभीर समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रशासन से अवैध कॉलोनियों के खिलाफ तत्काल और ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब देखना यह होगा कि देवरी और केसली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश का पालन अधिकारियों द्वारा किया जाता है या फिर सिर्फ कागजी कार्रवाई कर इस आदेश की लीपा-पोती कर दी जाती है। आम जनता और नागरिक संगठन इस पूरे मामले पर प्रशासन के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।

अविश्वास प्रस्ताव के बाद जारी है भुगतान

पार्षदों ने ली सख्त आपत्ति, नगर परिषद अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार पर रोक लगाई जाए

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। सिराली नगर परिषद की राजनीति गरमा गई है। अध्यक्ष अनिता अग्रवाल के खिलाफ 13 पार्षदों द्वारा जिला कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव सौंपे जाने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष के द्वारा अब भी वित्तीय अधिकारों का उपयोग कर लाखों रुपये के भुगतान किए जा रहे हैं, जिस पर पार्षदों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। पार्षदों ने नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी जयंत वर्मा को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाएं। पार्षदों का कहना है कि शासन के नियमों के अनुसार भुगतान का अधिकार वर्तमान सीएमओ को दिया गया है इसलिए सभी भुगतान उन्हीं के माध्यम से किए जाएं पार्षद पायल कुशवाहा ने बताया कि अध्यक्ष अनिता अग्रवाल अब अल्पमत में है। उनके साथ एक भी पार्षद नहीं है। इसके बावजूद वे नगर परिषद खातों से राशि निकलवा रही है जो पारदर्शिता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब अविश्वास प्रस्ताव लंबित है। तब अध्यक्ष को किसी भी प्रकार का वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो वे सामूहिक रूप से उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी देंगे। ज्ञापन देने वालों में पार्षद सुधा मालवीय, रेखा बांके, अनुराधा सोमानी, कालूराम सेजकर, भोलाशंकर कुशवाहा, रजित राजपूत, हयात पटेल सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। नगर परिषद में चल रहे इस मामले ने पूरे शहर में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। मामला अब सिराली नगर की आम जनता में भी चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है।

कलेक्टर ने कार्बाइड गन के भंडारण और क्रय- विक्रय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने विदिशा जिले की राजस्व सीमा में कार्बाइड गन के भंडारण और क्रय-विक्रय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर गुप्ता ने पटाखे, आतिशबाजी, लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे और कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, विक्रय नहीं करने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल से प्राप्त निर्देश जारी करने के बावजूद भी प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन तैयार कर विक्रय किये गए हैं, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अंशुल गुप्ता ने विदिशा जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति, संस्थाएं, व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखा आतिशबाजी, लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, विक्रय नहीं करेंगे और ना ही क्रय करेंगे। किसी भी प्रकार के अवैध प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा, स्टील, पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

सम्पादकीय

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीतिः विश्व पटल पर उभरते भारत की सशक्त पहचान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने बीते एक दशक में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। जिस भारत को कभी "सॉफ्ट पावर" तक सीमित माना जाता था, वह आज वैश्विक राजनीति, कूटनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में मजबूती से खड़ा है। मोदी सरकार ने न केवल भारत की पारंपरिक विदेश नीति को पुनर्परिभाषित किया है, बल्कि उसे 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप नई दिशा भी दी है। मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि भारत अब "वैश्विक एजेंडा सेट करने वाला देश" बन गया है। 2014 से पहले भारत की भूमिका अक्सर "प्रतिक्रियात्मक" होती थी, लेकिन आज भारत "नीति-निर्माण" की अग्रिम पंक्ति में है। चाहे G20 की अध्यक्षता हो, COP-26 जलवायु सम्मेलन हो या ग्लोबल साउथ समिट भारत की आवाज अब निर्णायक मानी जाती है।

मोदी की "वसुधैव कुटुम्बकम्" की विचारधारा ने भारतीय कूटनीति को नैतिक आधार दिया है। भारत अब केवल रणनीतिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व शांति, मानवीय मूल्यों और संतुलित विकास का संदेश लेकर चलता है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों से लेकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया तक भारत की छवि एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में बनी है। मोदी सरकार की विदेश नीति का पहला फोकस "नेबरहुड फर्स्ट" रहा। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों के साथ भारत ने न केवल विकास सहयोग बढ़ाया, बल्कि सुरक्षा, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के नए रास्ते खोले। बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता और जल बंटवारा समझौते की प्रगति, श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में भारत की त्वरित सहायता, और नेपाल में आपदा राहत के प्रयास—इन सबने भारत को एक "संकट में साथी" के रूप में स्थापित किया है। चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध भारतीय विदेश नीति की सबसे चुनौतीपूर्ण कड़ी रहे हैं। मोदी सरकार ने इन दोनों देशों के प्रति "दृढ़ लेकिन संवाद-आधारित" रुख अपनाया है।

डोकलाम और गलवान जैसी घटनाओं में भारत ने न केवल सीमा पर मजबूती दिखाई बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी चीन की आक्रामकता को उजागर किया। वहीं पाकिस्तान के संदर्भ में भारत ने आतंकवाद के प्रति "जीरो टॉलरेंस" नीति अपनाई सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक इसके उदाहरण हैं। इससे यह स्पष्ट संदेश गया कि भारत अब किसी भी आक्रामकता को चुपचाप नहीं सहेगा। मोदी सरकार के दौरान भारत-अमेरिका संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। QUAD गठबंधन, रक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर और प्रौद्योगिकी साझेदारी ने दोनों देशों को "रणनीतिक सहयोगी" बना दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के साथ भी भारत ने रक्षा और व्यापारिक संबंधों को गहराई दी है। फ्रांस के साथ राफेल सौदा और नौसेना सहयोग इसका स्पष्ट उदाहरण हैं।

यूक्रेन-रूस युद्ध के दौरान मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। भारत ने न तो रूस का विरोध किया, न ही पश्चिम के दबाव में आया- बल्कि "राष्ट्रीय हित" के आधार पर निर्णय लिया। भारत ने रूस से ऊर्जा खरीदी, लेकिन साथ ही यूक्रेन के प्रति मानवीय सहायता जारी रखी। यह "संतुलित कूटनीति" भारत की रणनीतिक परिपक्वता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन "यह युद्ध का युग नहीं है" पूरे विश्व में गूंजा और आज संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय संघ तक इस वाक्य को उद्धृत किया जाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, IMF, WHO और WTO जैसे वैश्विक संगठनों में अपनी आवाज को सशक्त किया है। G20 की अध्यक्षता भारत के कूटनीतिक आत्मविश्वास का प्रतीक बनी। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाना भारत की "वैश्विक समावेशिता" की नीति का उदाहरण था। इसके साथ ही, भारत अब "ग्लोबल साउथ" की आवाज बन चुका है विकासशील देशों के हितों की वकालत करता हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम "सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी" भी है। उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय को भारत की विदेश नीति का सशक्त दूत बना दिया है। न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी, टोक्यो और दुबई में भारतीय समुदायों से उनके संवादों ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर गौरव दिया। योग, आयुर्वेद, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और भारतीय भाषाओं के प्रसार ने सांस्कृतिक कूटनीति को नई ऊंचाई दी।

सियासी गहमागहमी

खंडेलवाल की टीम में न शामिल हो पाने का ग़म

राजनीति में पद का सुख कुछ वैसा ही होता है, जैसे गर्मी में एसी की ठंडक जिसे मिला वही चैन में और जिसे नहीं मिला, वह 'पार्टी सेवा' के पसीने में तर-बतर। हाल ही में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी टीम की घोषणा की, तो कई पुराने भाजपा नेताओं के चेहरे ऐसे उतर गए। मानो किसी ने उनके राजनीतिक सपनों की बिजली काट दी हो। कुछ तो ऐसे हैं जो अब भी पार्टी कार्यालय के गलियारों में 'कब बुलाएंगे खंडेलवाल जी' वाली उम्मीद लेकर टहल रहे हैं। वहीं कुछ अनुभवी नेताओं ने खुद को यह समझा लिया है कि "अभी समय नहीं आया, आगे अवसर बहुत हैं" हालांकि यह 'आगे' कब आएगा, यह खुद भगवान भी नहीं जानते। टीम से बाहर रहने वालों में से कुछ ने तो नए-नए सिद्धांत खोज निकाले हैं "हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, पद का मोह नहीं" ऐसा कहते वक्त उनके चेहरे पर वैसा ही दर्द झलकता है, जैसा मिठाई की थाली दूर जाते देख बच्चे के चेहरे पर होता है। अब पार्टी के अंदर ग़म का माहौल है, पर बाहर वही पुराना उत्साह 'सब अच्छा है, सब साथ है'।

कमलनाथ के कार्यों की दिल्ली में हुई प्रशंसा

दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में इन दिनों एक अनोखा माहौल देखने को मिला नेताओं के चेहरों पर मुस्कान थी, चाय के प्यालों में सुगंध थी और विषय था कमलनाथ के कार्यों की प्रशंसा। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने तो इतने जोश में तालियाँ बजाईं मानो मध्यप्रदेश फिर से कांग्रेस की झोली में लौट आया हो। किसी ने कहा "नाथ जी का अनुभव अमूल्य है", तो किसी ने जोड़ दिया "वे संगठन के स्तंभ हैं"। यह सुनते ही कुछ युवा नेता अपने मोबाइल में नाथ की पुरानी तस्वीरें ढूँढने लगे, ताकि सोशल मीडिया पर "हमारे प्रेरणास्रोत" लिखकर पोस्ट कर सकें। दिल्ली की हवा में अचानक 'संभावनाओं' की महक फैल गई कोई बोला, "राज्य में बदलाव की बयार है", तो दूसरा मुस्कुराया, "हां, लेकिन दिशा अभी तय नहीं।" इस सबके बीच कमलनाथ जी के समर्थक प्रसन्न थे कि कम से कम चर्चा तो चल रही है, क्योंकि राजनीति में आजकल प्रशंसा भी एक दुर्लभ पुरस्कार बन चुकी है। कुल मिलाकर, पार्टी दफ्तर में कमलनाथ की तारीफों की गूँज सुनाई दे रही है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर बस में आग लगने के भीषण हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है।

इस त्रासदी में जान गंवाने वाले सभी यात्रियों के शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

पन्ना जिले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी पंचम यादव ने 40-50 गुंडों के साथ मिलकर पुलिस दल पर कुल्हाड़ियों से हमला किया!

थानेदार और कॉन्स्टेबल को बंधक बना लिया गया और हालात ऐसे बने कि आठ पुलिसकर्मियों को हथियार छोड़कर भागना पड़ा!

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

परिश्रम, निष्ठा और अवसरों का प्रतिबिंब है धामी का जीवन

समता पाठक/जगत प्रवाह

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जीवन और राजनीतिक सफर कई मायनों में प्रेरणादायक है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उन परिश्रमों, निष्ठा और अवसरों का प्रतिबिंब है जिनसे एक छोटे हिमालयी गाँव से निकलकर उन्होंने उत्तराखण्ड की राजनीति का नेतृत्व संभाला है। धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जिले के तुंडी गाँव में हुआ। उनके पिता श्री शेर सिंह धामी भारतीय सेना में सेवा करते थे, जिससे परिवार के जीवन में अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का भाव बसा था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने विभिन्न सरकारी स्कूलों से पूरी की। आगे उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध (HRM & IR) में पोस्ट-ग्रेजुएशन और एलएलबी की डिग्री हासिल की। धामी ने 1990 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) में सक्रिय भूमिका निभाई और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सहायक संगठनों से जुड़े। 2002-08 के दौरान वे भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) उत्तराखण्ड के राज्य अध्यक्ष रहे। ये अनुभव उनके संगठनात्मक कौशल और जन-सेवा की समझ को गहरा करने का माध्यम बने। धामी पहली बार 2012 में उत्तराखण्ड विधानसभा के लिए खटीमा क्षेत्र से चुने गए। इसके बाद 2017 में पुनः विधायक बने। 2022 में उन्होंने चम्पावत निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव जीता। ये विधायी अनुभव उन्हें जन-प्रशासन, विकास और स्थानीय समस्याओं से सीधे रूबरू होने का अवसर मिले। 4 जुलाई 2021 को धामी उत्तराखण्ड के 10वें मुख्यमंत्री बने। उनकी उम्र सिर्फ 45 वर्ष थी, जिससे वह राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। बीसवीं सदी के उत्तराखण्ड की राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस पद पर रहते उन्होंने कई अहम निर्णय लिए, जैसे "ऑपरेशन कालनेमी" अभियान, परीक्षा-जाल का सामना और भ्रष्टाचार-रोधी कार्रवाइयाँ। धामी सरकार ने युवाओं, शिक्षा और सामाजिक कल्याण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने एवं खानापूर्ति रोकने का दावा किया है। साथ ही, विविध कल्याण योजनाएँ, विकलांगों के लिए अनुदान व वृद्धाश्रमों की घोषणा भी उनकी प्राथमिकताओं में रही। पर्यावरण-संवेदनशील राज्य के रूप में उत्तराखण्ड में धामी ने नदियों, पहाड़ी इलाकों और धार्मिक पर्यटन स्थलों के संरक्षण को भी महत्व दिया—जैसे हरिद्वार में "रिवर फेस्टिवल" का आयोजन। हालाँकि धामी के नेतृत्व को समर्थन मिला है, लेकिन उन्हें राज्य की भौगोलिक चुनौतियों, पर्यावरण-निर्माण संतुलन और वन एवं पर्यटन संसाधनों के प्रबंधन जैसे कठिन मुद्दों का सामना करना है। हिमालयी राज्य होने के नाते, धामी को विकास एवं संरक्षण के बीच संतुलन कायम रखना होगा।

पुष्कर सिंह धामी की कहानी इस बात की मिसाल है कि स्थानीय जीवन-प्रस्ताव, संगठन-अनुभव और समय की मांगें जब मिलती हैं, तो नेतृत्व आकार लेता है। उत्तराखण्ड में उनका नाम उन नेताओं में शामिल हुआ है जो युवा-उद्यमिता, सामाजिक न्याय और संस्थागत सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर धामी अपनी नीतियों को लगातार जमीन पर उतारते रहेंगे, लोक-विश्वास बनाए रखेंगे और हिमालयी प्रदेश की विशिष्ट चुनौतियों को समझ कर सक्रिय होंगे, तो वे न सिर्फ उत्तराखण्ड में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक मजबूत प्रतीक बन सकते हैं।

किसानों पर ऐसे अत्याचार तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुए, जिस तरह के अत्याचार भाजपा की सरकारें कर रही हैं : कमलनाथ

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश के 4.5 लाख के क़रीब किसानों को खाद आपूर्ति बंद कर देना ऐसी ही क्रूरता है। अब स्पष्ट हो रहा है कि पिछले कई महीने से मध्य प्रदेश में किसान खाद प्राप्त करने के लिए क्यों लाठियां खा रहे हैं? यह खाद का संकट नहीं था बल्कि सरकार की ओर से किसानों को खाद से वंचित करने का षड्यंत्र था।एक तरफ मेरे नेतृत्व में बनी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने 2019 में मध्यप्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया था, तो दूसरी तरफ़ भाजपा की सरकार है जो कर्ज माफ़ करना तो दूर, किसानों को डिफाल्टर बनाकर उबरन वसूली करने के लिए उन्हें खाद तक से वंचित कर रही हैं। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि किसानों के ऊपर जो भी बकाया राशि है उसे तत्काल माफ़ किया जाए और प्रदेश के एक-एक किसान को समुचित मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए।

छत्तीसगढ़ में जल-जीवन मिशन में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। राजधानी रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट यात्रियों को सुविधा देने के मामले में 8वें स्थान पर है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे (ASQ) 2025 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) की रिपोर्ट में देश के टॉप-10 एयरपोर्ट्स में रायपुर एयरपोर्ट ने 8वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल भी इसी अवधि में रायपुर एयरपोर्ट 8वें स्थान पर था। सर्वे में यात्रियों से 33 बिंदुओं पर फीडबैक लिया जाता है, जिसमें टर्मिनल, साफ-सफाई, पानी, बैठने की व्यवस्था, फूड स्टॉल, यात्री सुविधाएं और कर्मचारियों का व्यवहार शामिल हैं।

रायपुर एयरपोर्ट से 20-25 हजार यात्री करते हैं सफर

सर्वे में तकनीकी और आधारभूत सुविधाओं का भी मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कनेक्टिविटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइनबोर्ड, टर्मिनल भवन में चलने की दूरी, चेकिंग काउंटर, पार्किंग क्षेत्र, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाएं। रायपुर एयरपोर्ट से हर हफ्ते औसतन 20-25 हजार यात्री आते और जाते हैं। यह सर्वे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) द्वारा कराया जाता है और उन एयरपोर्ट्स पर लागू होता है, जहां सालाना यात्रियों की संख्या 18 लाख से अधिक होती है। एशिया-पैसफिक क्षेत्र के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट्स में यह मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें भारत के 16 प्रमुख एयरपोर्ट्स शामिल हैं। रायपुर एयरपोर्ट इस रैंकिंग में 72वां स्थान रहा।

छत्तीसगढ़ के बीजीपुर में नक्सलियों ने की दो ग्रामीणों की निर्मम हत्या

-संवाददाता

जगत प्रवाह. बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजीपुर में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक, उसूर थाना क्षेत्र के नेलाकांकेर गांव में नक्सलियों ने धारदार हथियार से दो ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेलाकांकेर गांव निवासी रवि कट्टम (25) और तिरुपति सोढी (38) की नक्सलियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि नक्सलियों के एक दल ने नेलाकांकेर निवासी कट्टम और सोढी की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस दल को घटना स्थल के लिए रवाना किया गया है। बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर संभाग के अलग-अलग स्थानों पर नक्सली ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं।

बीजेपी कार्यकर्ता की भी हुई थी हत्या

इससे पहले जिले में 14 अक्टूबर को नक्सलियों ने भाजपा कार्यकर्ता की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इलमिड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुजालकांकेर गांव में नक्सलियों ने सत्यम पुनेम की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुनेम क्षेत्र में भाजपा के मंडल कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। उन्होंने बताया कि शव के करीब से पर्चा भी बरामद किया गया है। पुनेम की हत्या की जिम्मेदारी कथित तौर पर नक्सलियों की महेंद्र एरिया कमेटी ने ली है। पर्चे में पुनेम के मुखबिर होने का आरोप लगाया गया है, वहीं उसे बार—बार समझाइश देने का भी उल्लेख किया गया है। इस घटना के साथ बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर संभाग के अलग-अलग स्थानों पर इस साल अब तक माओवादी हिंसा में लगभग 40 लोगों की जान जा चुकी है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 के बीच संभाग में अलग-अलग घटनाओं में 11 भाजपा नेताओं की हत्या कर दी गई।

दिवाली बाद गहराया देशव्यापी प्रदूषण

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

देशव्यापी प्रदूषण गहराने की रिपोर्ट भले ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दी है, लेकिन यह आशंका पूर्व से ही थी कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में वायु प्रदूषण में वृद्धि दर्ज की जाएगी? सांस, दमा और अस्थमा के रोगियों को परेशानी होगी। क्योंकि वायु गुणवत्ता बद से बदतर होने की श्रेणी में पहुंच जाएगी। यह स्थिति तब है, जब दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से चिंतित शासन-प्रशासन तो रहता ही है, सर्वोच्च न्यायालय की चिंता भी पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर देखी जाती रही है। इसलिए न्यायालय ने हरित पटाखों को चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन निगरानी की ऐसी कोई विधि सरकार के पास नहीं है कि हरित पटाखों की ओट में सामान्य पटाखे चलाए ही न जाएं? ग्रीन पटाखों को लेकर यह धारणा है कि तुलनात्मक रूप में वे सामान्य पटाखों से प्रदूशण मुक्त हैं, लेकिन इनकी पहचान आसान नहीं है। दरअसल पटाखे इतनी बड़ी मात्रा में पूरे देश में बनते हैं कि इनकी गुणवत्ता एवं मानक की परख करना असंभव है। इस दायित्व के निर्वहन की जवाबदेही 'राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान' (नीरी) को है अवश्य, किंतु मानक निर्धारण की नैतिक जुम्मेबारी पटाखे निर्माताओं और फिर उन पर निगरानी सरकारी तंत्र की है, जो अकसर दायित्व निभाने में लापरवाह रहता है। इसीलिए वायु गुणवत्ता प्रदूषण का सूचकांक दिल्ली में कई स्थानों पर एक्यूआई 351 के पार दर्ज किया गया। हरियाणा के जींद में यह प्रदूशण सबसे अधिक 421 पर दर्ज हुआ है। यही हकीकत हर साल बनी रहती है।

रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषित हवा बह रही है। दस शहरों में दिल्ली 10वें नंबर पर है। शेष 9 शहरों में 8 हरियाणा और एक राजस्थान का है। यानी दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा की हवा अब देश के राज्यों में सबसे ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। सीपीसीबी देश के 271 नगरों की हवा की गुणवत्ता की निगरानी रखता है। इनमें से 20 नगरों की वायु इस बार दिवाली के बाद अच्छी रही है, जबकि 54 नगरों में संतोषजनक और 103 नगरों में मध्यम स्तर की रही है। दीपावली के बाद दिल्ली में पीएम 2.5 का चौबीस घंटे में औसत 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ, जो पिछले पांच साल में सबसे अधिक है। यह स्थिति तब है, जब हरियाणा एवं पंजाब में 2024 के अनुपात में पराली जलाने की घटनाएं 77.5 प्रतिशत घटी हैं। यहां यह जानने की जरूरत है कि पीएम 2.5 की मात्रा एक्यूआई का ही एक भाग है। एक्यूआई वायु में मौजूद 2.5 पीएम-10 ओजोन व अन्य प्रदूशणकारी गैसों की मात्रा को गणना करके तय किया जाता है। दिल्ली में वैसे भी ठंड की शुरूआत होने के साथ ही हवा गहराने लगती है, और प्रदूषण का संकट बढ़ने लगता है। यह स्थिति लगभग प्रतिवर्ष निर्मित होती है, लेकिन विडंबना है कि इन तथ्यों को जानते-बूझते सरकार नजरअंदाज कर देती है। इसलिए प्रदूषण सुधार के जो चंद उपाय किए जाते हैं, वे बेअसर साबित होते हैं। अतएव प्रदूषण उत्सर्जन के कारण यथावत बने रहते है।

हम जानते है कि बच्चे और किशोर आतिशबाजी के प्रति अधिक उत्साही होते हैं और उसे चलाकर आनंदित भी होते हैं। जबकि यही बच्चे वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लेते हैं। खतरनाक पटाखों की चपेट में आकर अनेक बच्चे आंखों की रोशनी और हाथों की अंगुलियां तक खो देते हैं। बावजूद समाज के एक बड़े हिस्से को पटाखा मुक्त दिवाली रास नहीं आती है। इसीलिए अदालती आदेश के बाद यह बहस चल पडती है कि दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक स्तर 2.5 पीएम पर प्रदूशण पहुंचने का आधार क्या केवल पटाखे हैं? सच तो यह है कि इस मौसम में हवा को प्रदूशित करने वाले कारणों में बारुद से निकलने वाला धुआं एक कारण जरूर है, लेकिन दूसरे कारणों में दिल्ली की सड़कों पर वे कारें भी हैं, जिनकी बिक्री निरंतर उछाल पर है। नए भवनों की बढ़ती संख्या भी दिल्ली में प्रदूशण को बढ़ा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाया जाना भी दिल्ली की हवा को खराब करने का एक कारण है। इस कारण दिल्ली के वायुमंडल में पीएम 2.5 का स्तर बढ़ जाता है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर वायु का स्तर 10 पीएम से कम होना चाहिए। पीएम वायु में घुले-मिले ऐसे सूक्ष्म कण है, जो सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचकर अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं।

वायु के ताप और आपेक्षिक आद्रता का संतुलन गड़बड़ा जाने से हवा प्रदूषण के दायरे में आने लगती है। यदि वायु में 18 डिग्री सेल्सियस ताप और 50 प्रतिशत आपेक्षिक आर्द्रता हो तो वायु का अनुभव सुखद लगता है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक में वृद्धि, वायु को खतरनाक रूप में बदलने लगती है। 'राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मूल्यांकन कार्यक्रम' (एनएसीएमपी) के मातहत 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल' वायु में विद्यमान ताप और आद्रता के घटकों को नापकर यह जानकारी देता है कि देश के किस नगर में वायु की शुद्धता अथवा प्रदूषण की क्या स्थिति है। मापने की इस विधि को 'पार्टिकुलेट मैटर' मसलन 'कणीय पदार्थ' कहते हैं। प्रदूषित वायु में विलीन हो जाने वाले ये पदार्थ हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाईऑक्साइड। सीपीसीबी द्वारा तय मापदंडों के मुताबिक उस वायु को अधिकतम शुद्ध माना जाता है, जिसमें प्रदूषकों का स्तर मानक मान के स्तर से 50 प्रतिशत से कम हो। इस लिहाज से दिल्ली समेत भारत के जो अन्य नगर प्रदूषण की चपेट में हैं, उनके वायुमंडल में सल्फर डाईऑक्साइड का प्रदूशण कम हुआ है, जबकि नाइट्रोजन डाईऑक्साइड का स्तर कुछ बड़ा है।

सीपीसीबी ने उन नगरों को अधिक प्रदूषित माना है, जिनमें वायु प्रदूशण का स्तर निर्धारित मानक से डेढ़ गुना अधिक है। यदि प्रदूषण का स्तर मानक के तय मानदंड से डेढ़ गुना के बीच हो तो उसे उच्च प्रदूषण कहा जाता है। और यदि प्रदूषण मानक स्तर के 50 प्रतिशत से कम हो तो उसे निम्न स्तर का प्रदूषण कहा जाता है। वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले कणीय पदार्थ, कई पदार्थों के मिश्रण होते हैं। इनमें धातु, खनिज, धुएं, राख और धूल के कण मिले होते हैं। इन कणों का आकार भिन्न-भिन्न होता है। इसीलिए इन्हें वर्गीकृत करके अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी के कणीय पदार्थों को पीएम-10 कहते हैं। इन कणों का आकार 10 माइक्रोन से कम होता है। दूसरी श्रेणी में 2.5 श्रेणी के कणीय पदार्थ आते हैं। इनका आकार 2.5 माइक्रोन से कम होता है। ये कण शुष्क व द्रव्य दोनों रूपों में होते हैं। वायुमंडल में तैर रहे दोनों ही आकारों के कण मुंह और नाक के जरिए श्वास नली में आसानी से प्रविष्ट हो जाते हैं। ये फेफड़ों तथा हृदय को प्रभावित करके कई तरह के रोगों के जनक बन जाते हैं। आजकल नाइट्रोजन डाईऑक्साइड देश के नगरों में वायु प्रदूशण का बड़ा कारक बन रही है।

औद्योगिक विकास, बढ़ता शहरीकरण और उपभोगक्तावादी संस्कृति, आधुनिक विकास के ऐसे नमूने हैं, जो हवा, पानी और मिट्टी को एक साथ प्रदूषित करते हुए समूचे जीव-जगत को संकटग्रस्त बना रहे हैं। लेकिन दिवाली पर रोशनी के साथ आतिशबाजी छोड़कर जो खुशियां मनाई जाती है, उनका व्यावहारिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पक्ष भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अकेली दिल्ली में पटाखों का कई हजार करोड़ का कारोबार होता है, जो कि देश में होने वाले कुल पटाखों के व्यापार का 25 फीसदी हिस्सा है। इससे छोटे-बड़े हजारों थोक व खेरीज व्यापारी और पटाखा उत्पादक मजदूरों की साल भर की रोजी-रोटी चलती है। इस लिहाज से इस व्यापार पर प्रतिबंध के व्यावहारिक पक्ष पर भी गौर करने की जरूरत है? यह अच्छी बात है कि शीर्ष न्यायालय सामान्य पटाखों पर रोक के साथ हरित पटाखे चलाने को प्रोत्साहित कर रही है। इससे स्वदेशी हरित पटाखा उद्योग विकसित होगा और भविष्य में दिल्ली को प्रदूषित महानगर होने की श्रेणी से भी मुक्ति मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद वित्त विभाग की भी मिली मंजूरी, पांच हजार नए पदों पर भर्ती के लिए जल्द जारी होगा

(पेज 1 का शेष)

साथ ही, यह पहल प्रदेश में शिक्षण के स्तर को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा को सर्वांगीण विकास का आधार मानते हुए लगातार निवेश कर रही है। स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण से लेकर छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन और छात्र हितैषी योजनाओं तक, सरकार का फोकस हर स्तर पर शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना है। शिक्षकों की यह नई भर्ती उसी दीर्घकालिक दृष्टि का हिस्सा है, जो 'विकसित छत्तीसगढ़' के विजन को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। इस निर्णय से जहाँ शिक्षा प्रणाली को नई ऊर्जा मिलेगी, वहीं हजारों युवाओं के सपनों को साकार करने का मार्ग भी खुलेगा। यह पहल मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 'शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़' की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी।

लक्ष्य तक वही पहुँचता है, जो सही समय पर लेता है 'निर्णय

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

जीवन अवसरों और चुनौतियों का अनवरत सिलसिला है और इनके बीच सबसे निर्णायक सेतु है- निर्णय। हम अक्सर किसी चौराहे पर खड़े होते हैं। 'हाँ' कहें या 'ना', सुरक्षित मार्ग चुनें या जोखिम लें, कदम आगे बढ़ाएँ या यथास्थिति बनाए रखें। यह क्षणिक ठहराव- यदि लंबा खिंच जाए- धीरे-धीरे जीवन की गति और ऊर्जा को सोख लेता है। अनिर्णय व्यक्ति को निष्क्रियता की ओर धकेलता है और निष्क्रियता अंततः ठहराव का कारण बनती है। एक पूर्व पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ निभा चुका व्यक्ति होने के नाते मेरा अनुभव यही कहता है निर्णय लेना ही नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेना सफलता का सबसे बड़ा तत्व है। इतिहास साक्षी है कि समयबद्ध और साहसिक निर्णयों ने व्यक्तियों, संस्थाओं और राष्ट्रों की दिशा बदल दी।

निर्णयः अस्तित्व का आधार और प्रेरणा की धुरी

निर्णय केवल विकल्प चुनना नहीं, भविष्य की रूपरेखा तय करना है। जिस क्षण हम साहसिक निर्णय लेते हैं, उसी क्षण हम अपने आने वाले अवसरों की दिशा भी चुन लेते हैं।

सही निर्णयः विवेक और दूरदृष्टि का संगम

निर्णय लेना एक बात है, सही निर्णय लेना एक कला है। यह तीन बातों पर आधारित होता है—

-स्थिति का यथार्थपरक विश्लेषण।
-विकल्पों का संतुलित मूल्यांकन।
-दीर्घकालिक प्रभाव को समझना।

सफलता की गारंटी केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में लिया गया विवेकपूर्ण निर्णय होती है। मेहनत इंजन है, दिशा निर्णय तय करता है।

–स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में बोलने का निर्णय लिया- भारतीय अध्यात्म की आवाज़ विश्व मंच पर अजर-अमर हो गई।

– महात्मा गांधी ने चंपारण में उतरने का निर्णय लिया- स्वाधीनता संग्राम की धारा ही बदल गई।

–असंख्य युवाओं ने सुरक्षित नौकरी छोड़कर स्टार्टअप का निर्णय लिया- अपना भविष्य गढ़ा और हजारों के लिए रोज़गार के द्वार खोले।

हर बड़ा परिवर्तनः व्यक्तिगत हो या राष्ट्रीय- एक निर्णायक कदम से ही शुरू होता है।

समय पर निर्णयः अवसरों को थामने की कुंजी

अवसर दरवाज़ा खटखटाते हैं, पर इंतज़ार नहीं करते। जो "सोचते" रह गए, वे पीछे छूट गए; जो "निर्णय" ले बैठे, वही आगे बढ़े।

देरी की तीन कीमतें होती हैं-
(1) अवसर का पलायन,
(2) प्रतिस्पर्धा की बढ़त,
(3) आत्मविश्वास का क्षय।

यही कारण है कि समय पर लिया गया साधारण निर्णय भी देरी से लिए गए श्रेष्ठ निर्णय से अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है।

जीवन के हर मोर्चे पर निर्णय की भूमिका

विद्यार्थी के लिए कुछ अतिरिक्त घंटे पढ़ने या सही करियर-विषय चुनने का निर्णय भविष्य के दरवाजे खोलता है।

उद्यमी या व्यापारी के लिए बाजार को समझकर नई साझेदारी का त्वरित निर्णय (जैसे किसी सक्षम भागीदार से टाई-अप या रणनीतिक निवेश) मंदी में भी विकास का इंजन बन सकता है। पेशेवर जीवन में प्राथमिकताएँ तय करने और समय प्रबंधन के निर्णय से न केवल उत्पादकता बढ़ती है बल्कि आत्मविश्वास भी। गृहस्थ जीवन में शिक्षा, पोषण और बचत को लेकर सही निर्णय पूरे परिवार को सुरक्षित आधार देता है। सामाजिक जीवन में गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठाने का निर्णय एक सजग नागरिक गढ़ता है। राष्ट्र की शक्ति उसके नागरिकों के छोटे-बड़े, समयबद्ध निर्णयों में ही निहित होती है।

नेतृत्व का शिखरः जब एक निर्णय लाखों को प्रभावित करता है

नेतृत्व का बड़ा दायित्व निर्णय लेना है- अपने लिए और उन सबके लिए जो उस पर निर्भर हैं। चाहे जनप्रतिनिधि का जनहित में साहसिक कदम हो या किसी प्रशासनिक अधिकारी का नीतिगत निर्णय- एक पल की अनिर्णय स्थिति लाखों जीवनों को प्रभावित कर सकती है। निर्णय में देरी से नीतियाँ अटकती हैं, योजनाएँ ठहरती हैं और सपने अधूरे रह जाते हैं। गलत निर्णय से डरना नहीं, उससे सीखना जरूरी है। निर्णय गलत हो सकते हैं पर निर्णय न लेना सबसे बड़ी भूल है। गलत निर्णय सुधारे जा सकते हैं; अनिर्णय की स्थिति नहीं। जो गिरकर भी उठते हैं, गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं वही विजेता बनते हैं। जीतने और हारने वालों में फर्क यही होता है। अपना निर्णय स्वयं लेकर अपना भाग्य लिखिए

जीवन में निर्णय से कोई नहीं बच सकता। या तो परिस्थितियाँ आपके लिए निर्णय लेंगी, या आप अपने विवेक और साहस से अपना भाग्य स्वयं लिखेंगे। सही निर्णय, समय पर निर्णय और साहसिक निर्णय- यही जीवन को दिशा और मंज़िल देते हैं। 'कल' की दिशा हमेशा 'आज' लिए गए एक निर्णायक कदम से तय होती है। उठिए, सोचिए, और एक स्पष्ट निर्णय के साथ अपने जीवन की नई दिशा तय कीजिए।

जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक ख़तरा है। यह अब कोई दार्शनिक बहस नहीं, बल्कि हर शाम की पत्रिका, हर अस्पताल की रिपोर्ट और हर किसान की बातचीत का व्यावहारिक सच बन गया है। जब धरती की सतह गरम होती है, जब समुद्र उफान पर आता है और जब मौसमी पैटर्न उखड़ते हैं, तो उसका सीधा, अमिट और अक्सर जानलेवा असर मनुष्यों की सेहत पर पड़ता है। इस खतरे को नज़र अंदाज़ करना न केवल वैज्ञानिक लापरवाही होगी बल्कि यह मानवता के सबसे कमजोर वर्गों के साथ सीधे विश्वासघात करने जैसा है। जलवायु परिवर्तन न केवल पृथ्वी के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चुनौती है, बल्कि यह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर और व्यापक खतरा बन चुका है। आने वाले दशकों में इसका असर स्वास्थ्य प्रणालियों पर बहुत गहरा पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2 अरब लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता, जिससे रोग फैलते हैं।

सबसे पहले, भीषण गर्मी (हीटवेव) का असर स्पष्ट और खतरनाक है। पिछले कुछ दशकों में हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ी हैं। अत्यधिक गर्मी से हृदय-श्वास संबंधी समस्याएँ और किडनी की बिमारियाँ तेजी से बढ़ती हैं। बूढ़े लोग, छोटे बच्चे और वे जो ग़रीबी में रहते हुए शारीरिक श्रम करते हैं जैसे खेतों के मजदूर, सड़क किनारे के कामगार आदि इनके लिए यह सीधी जानलेवा स्थिति है। अत्यधिक तापमान में काम करने से थकावट, निर्जलीकरण और घातक हीट स्ट्रोक होता है और जब बिजली व्यवस्था ठप्प हो और कूलिंग की सुविधा न हो, तो परिणाम भयावह हो सकता है। इससे अस्पतालों पर तत्काल दबाव पड़ता है और अस्पतालों की सीमित क्षमता जल्दी भर जाती है।

दूसरा बड़ा असर संक्रामक रोगों में है। जलवायुःपरिवर्तन ने रोग फैलाने वाले वेक्टर जैसे मच्छर, टिक, अन्य कीट आदि के व्यवहार और वितरण को बदला है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ज़ीका जैसे रोग अब उन क्षेत्रों में भी दस्तक दे रहे हैं जहाँ पहले ये मौजूद नहीं थे। गर्म और नम मौसम ने मच्छरों को लंबी आयु और तेज़ प्रजनन चक्र दिया है, जिससे रोग का प्रसार अधिक व्यापक और तेज हुआ है। इसके अलावा, बाढ़ और सुनामी जैसी दुर्घटनाओं के बाद स्वच्छ पानी और बेसिक सैनिटेशन तक पहुंच बाधित होती है, जिससे जलजन्य रोग फैलने का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य तंत्र पर न केवल रोग-भार बढ़ता है, बल्कि रोगों के इलाज और रोकथाम के लिए आवश्यक संसाधनों की मांग भी असमय और असामान्य रूप से बढ़ जाती है।

खाद्य सुरक्षा और पोषण पर भी जलवायु परिवर्तन का गहरा असर है। चरम मौसमी घटनाएँ जैसे सूखा, बाढ़, आंधी आदि फसल उगाने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। उपज में गिरावट का सीधा अर्थ है बाजारों में अनाज, फल और सब्ज़ियों की कमी और बढ़ी कीमतें। यदि पोषण कम होता है, तो खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, जिससे संक्रमण और मृत्यु दर बढ़ सकती है। नमक के बढ़ते स्तर (सालिनिटी) और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में कमी भी लंबी अवधि में समुदायों की स्वास्थ्य-क्षमता को छीन लेती है। भूख के साथ जुड़ी नुकसानदेह मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ जैसे तनाव, अवसाद आदि भी बढ़ती हैं। इस तरह, खाद्य असुरक्षा का प्रभाव केवल शारीरिक कुपोषण तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक और मानसिक परतों में भी फैलता है।

मानव प्रवासन और विस्थापन भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब तटीय इलाक़ों में समुद्र का स्तर बढ़ता है या बार-बार आने वाली बाढ़ घर-बार तहस-नहस कर देती है, तो परिवारों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकाने ढूँढने पड़ते हैं। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन का यह दबाव स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ डालता है। ना तो शरणार्थी शिविरों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ होती हैं, ना ही नए बसे समुदायों में सतत स्वास्थ्य निगरानी और टीकाकरण व्यवस्था। इससे संक्रामक रोगों का फैलाव, मानसिक आघात और महिलाओं व बच्चों की विशेष सुरक्षा चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

स्वास्थ्य सेवाएँ और बुनियादी ढाँचा स्वयं ही जलवायु के असर से प्रभावित हैं। अस्पताल, क्लीनिक और दवा-भण्डार बाढ़, आँधियों और ऊष्मा-लहरों के कारण काम बंद कर सकते हैं; आपूर्ति श्रृंखला टूट सकती है और स्वास्थ्यकर्मी स्वयं असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हो जाते हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य प्रणालियों को क्लाइमेट-रेज़िलियंट (जलवायु-लचीला) बनाना आज प्राथमिकता बननी चाहिए। इससे तात्कालिक आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ेगी और दीर्घकालीन स्वास्थ्य लक्ष्यों का संरक्षण होगा।

एक और अक्सर अनदेखा पहलू है और वह है मानसिक स्वास्थ्य। जब लोग अपने घर, उपस्थिति-समुदाय या आजीविका खो देते हैं; जब फसल बार-बार नष्ट होती है, जब मौसम अनिश्चित और भयावह हो तो इन सबका दिमाग और मन पर गहरा असर पड़ता है। चिंता, अनिद्रा, अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। जलवायु चिंताएँ नई पीढ़ियों में एक उभरता हुआ मानसिक स्वास्थ्य संकट बन रही हैं। एक ऐसा संकट जिसका इलाज केवल मनोचिकित्सा नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहारा और समुदायिक समर्थन के समन्वित उपायों से ही संभव है। सबसे दुखद बात यह है कि यह संकट असमान है। जो देश और समुदाय सबसे कम योगदान देते हैं जैसे कम आय वाले देश, तटीय गांव, आदिवासी समुदाय आदि।व ये सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ग्लोबल नॉर्थ के औद्योगिक देशों द्वारा निकलने वाले उत्सर्जन से ग्लोबल साउथ के लोग हर रोज़ अपने अस्तित्व, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए जलवायु न्याय का मुद्दा स्वास्थ्य नीतियों में अभिन्न होना चाहिए। यह सिर्फ़ पर्यावरण नीति नहीं, बल्कि मानवाधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य की भी बात है।

उत्सर्जन कम करना इसका एक समाधान है। इसके अलावा वैज्ञानिक, सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ-साथ नागरिक समाज को भी अपने-अपने स्तर पर बदलाव करने होंगे। ऊर्जा प्रणाली को स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से मोड़ना, परिवहन के कार्बन उत्सर्जन कम करना, औद्योगिक प्रक्रियाओं में ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाना, ये सभी बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान करेंगे। इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर adaptation के उपायों जैसे जल संरक्षण, मौसम-समझ आधारित कृषि, गर्मी की लहरों के लिए अलर्ट सिस्टम, स्वास्थ्य क्लीनिकों का क्लाइमेट-प्रूफिंग की तत्काल आवश्यकता है। स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए कुछ ठोस कदम सुझाने योग्य हैः पहले, रोग निगरानी नेटवर्क का दायरा बढ़ाया जाए ताकि नए और पारंपरिक रोगों का त्वरित पता चल सके। दूसरे, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण और संसाधन बढ़ाएं ताकि वे क्लाइमेट-ड्रिवन रोगों से निपटने में सक्षम हों। तीसरा, आपातकालीन स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को टिकाऊ और स्थानीयकृत बनाया जाए ताकि बाढ़ या तूफ़ान के समय दवाइयाँ और उपकरण उपलब्ध रहें। चौथा, समुदाय आधारित स्वास्थ्य शिक्षण को तवज्जो दें। लोगों को खुद जल-विहार, स्वच्छता और रोग-रोकथाम की साधारण उपायों के बारे में सशक्त करें। राजनीतिक नेतृत्व यहाँ निर्णायक भूमिका निभाता है। जलवायु और स्वास्थ्य की इंटरसेक्शन को राष्ट्रीय नीति में प्रमुखता देनी होगी। बजट आवंटन ऐसी नीतियों को समर्थन दे। न केवल हरित ऊर्जा पर, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य-इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट-रेज़िलियंट बनाने पर भी। वैश्विक मंचों पर भी अमीर देशों को उन सीमांत समुदायों के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी समर्थन देना चाहिए, जो सबसे अधिक प्रभावित हैं पर कम सक्षम हैं। नागरिकों का भी दायित्व कम नहीं। व्यक्तिगत स्तर पर ऊर्जा-बचत, कम कार्बन जीवनशैली, पौधारोपण और स्थानीय समुदायों में सक्रिय भागीदारी से बड़े पैमाने पर असर पड़ेगा। मीडिया और शिक्षा संस्थाओं को जनचेतना फैलाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

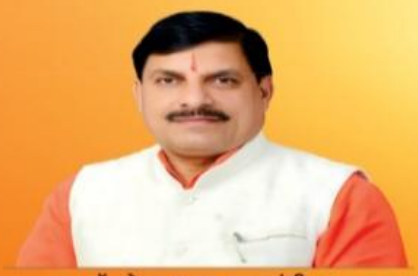

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश
अनंत संभावनाएं

उद्योग एवं रोज़गार वर्ष 2025

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रदेश के कृषि फीडर्स को
सौर ऊर्जीकृत करने का अभियान

नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध होता
मध्यप्रदेश

व्यापक निवेश अवसर

सूर्य मित्र
कृषि फीडर योजना

योजना के प्रमुख उद्देश्य

- मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी को कम मूल्य पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराना
- ट्रांसमिशन हानि कम करना एवं सीधे खपत स्थल पर बिजली पहुंचाना
- 33/11 केवी उपकेंद्रों पर ओवरलोडिंग, लो-वोल्टेज और पावर कट की समस्या कम करना
- किसान को सिंचाई के लिये दिन में बिजली उपलब्ध कराना

नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार

- सब-स्टेशन की 100% क्षमता तक की परियोजनाओं की स्थापना
- परियोजनाओं को पीएम कुसुम-सी योजनांतर्गत उपलब्ध केंद्रीय अनुदान का लाभ लेने का विकल्प
- 1900 से अधिक विद्युत सबस्टेशन एवं 14500 मेगावॉट क्षमता सौर परियोजनाओं के चयन हेतु उपलब्ध
- पीएम कुसुम योजना में 3.45 लाख पम्प का लक्ष्य
- वोकल फॉर लोकल - स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश एवं रोज़गार सृजन का उचित अवसर
- वित्त पोषण की सुगमता के लिए बैंकों से समन्वय
- परियोजनाओं में AIF के तहत 7 वर्षों तक 3% ब्याज में छूट
- Reactive Power प्रबंधन से अतिरिक्त आय

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. जनसम्पर्क/2025

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)